शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 19-26 जून 2023 मूल्य पांच रूपए

कांग्रेस की गारंटीयों पर सुक्खू सरकार की परफॉरमैन्स से हाईकमान चिन्ता में

- सुक्खू सरकार की परफॉरमैन्स का चुनावी राज्यों पर असर पड़ना तय
- शिमला में प्रस्तावित विपक्ष की बैठक में यह परफॉरमैन्स स्वतः ही सामने आ जायेगी
- गारंटीयां तो दूर सत्ता परिवर्तन का एहसास तक नहीं करवा पायी है सरकार
- भाजपा काल का प्रशासन ही हावी है शीर्ष से लेकर फील्ड तक

शिमला/शैल। जब से कांग्रेस हाईकमान द्वारा करवाये गये सर्वे में यह सामने आया है कि हिमाचल में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है और वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है तब से प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गयी है। यह चर्चा में आया है कि प्रदेश के हालात पर कॉल सिंह ने एक रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है जिसमें तेईस विधायकों और चार मंत्रियों के हस्ताक्षर हैं। यह चर्चा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भी दिल्ली गये। दिल्ली में मुख्यमंत्री की पहले दिन प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला फिर राहुल गांधी तथा देर शाम के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। दूसरे दिन फिर राजीव शुक्ला से दो दौर की बैठक हुई। अगले दिन प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। इसी दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव भी दिल्ली पहुंचे। शायद वह चिदम्बरम वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली गये थे क्योंकि इसमें वह भी सह अभियुक्त हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह मामला निर्णायक बिन्दु पर पहुंच जायेगा। इस समय सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।

मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार और विभिन्न निगमों/बोर्डो में संभावित ताजपोशीयों को लेकर चर्चाएं गर्म हो गयी हैं। लेकिन इसी दौरान छः बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्री शिमला में मौजूद होने के बावजूद नहीं आये उससे न चाहते हुये भी प्रदेश की जनता में यह संदेश चला गया कि सरकार और संगठन में सब अच्छा नहीं चल रहा है। स्व. वीरभद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की जनता के दिलों में जो स्थान है उसे काम के सहारे भी विस्थापित करने में लम्बा समय लगेगा। इसलिये सार्वजनिक आचरण में जरा सा भी यह संकेत जाना कि उनकी अहमियत कम करने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा। अभी तो अगले विधानसभा चुनाव में भी वीरभद्र सिंह प्रसांगिक रहेंगे। लेकिन इस मौके पर जो सियासत की गयी है उससे सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। यह सब कुछ रिपोर्ट हुआ है और दिल्ली तक पहुंचा है।

दूसरी ओर वित्तीय संकट चलते कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान तक नहीं हो पा रहा है। हजारों कर्मचारी हर महीने प्रभावित हो रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जायेगी। यह शीर्ष प्रशासन ने भी मानना शुरू कर दिया है। इसी संकट के चलते सरकार गारंटीयां लाग नहीं कर पा रही है। ओ.पी.एस. बहाली से बड़ा मुद्दा 2021 में हुये वेतन मान संशोधन के फलस्वरूप 2016 से 2021 तक सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को इस संशोधन के अनुसार एरियर का भुगतान न होना बनता जा रहा है। क्योंकि ओ.पी.एस. का असर सरकार के इस कार्यकाल में नहीं के बराबर पड़ना है। आरोप है कि सरकार के पास कर्मचारियों का 2000 करोड़ जमा है जिस पर सरकार चार सौ करोड़ से ज्यादा ब्याज कमा चुकी है। वित्तीय स्थिति के कारण यदि कर्मचारियों को भुगतान तक नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा किस आधार पर की जा रही है? क्या कर्ज लेकर बड़े ठेकेदारों को ही भुगतान किये जा रहे हैं यह सवाल उठने शुरू हो गये हैं। दिल्ली तक यह जानकारीयां भी पहुंच चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री इस सबको भ्रामक प्रचार कहकर जो नकारने का प्रयास कर रहे हैं उससे स्थिति और भी हास्य पद होती जा रही है।

भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर कारवाई न करना सरकार की नीति बन गयी है। बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में यह और भी रोचक हो जायेगा कि जिन चार प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भी जब हिमाचल की तर्ज पर कांग्रेस गारंटीयां घोषित करेगी तो वहां पर विपक्ष हिमाचल की सुक्खू सरकार की परफॉरमैन्स का लेखा-जोखा जनता के सामने रखकर कांग्रेस को परेशानी में डाल देगा। अभी जुलाई में विपक्ष की शिमला में बैठक होने जा रही है उस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को जब अपने स्तर पर ही प्रदेश सरकार की परफॉरमैन्स कि यह व्यवहारिक जानकारी मिल जायेगी कि यह सरकार गारंटीयां लागू करना तो दूर बल्कि समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही है तब हाईकमान के लिये यह एक बहुत ही असहज स्थिति बन जायेगी। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह यह सरकार अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ही सत्ता परिवर्तन का एहसास नहीं करवा पायी है उससे ज्यादा हास्यपद और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा काल के प्रशासन को ही यह सरकार शीर्ष पर क्यों बैठाये हुए हैं इस सवाल का जवाब खोजने में शायद अब हाईकमान भी लग गयी है क्योंकि हिमाचल का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा हाईकमान इससे चिन्तित है।

राज्यपाल ने प्रो-बॉक्सिंग टूर्नामैंट का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रो-बॉक्सिंग

टूर्नामैंट का शुभारम्भ किया। यह प्रतियोगिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की स्मृति में उनकी जयंती पर आयोजित की गई।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्व. वीरभद्र सिंह ने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया है। राज्य में विकास के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से जहां प्रदेश के नवोदित बॉक्सिंग खिलाड़ियों को मंच प्राप्त होगा, वहीं अन्य युवा भी इस खेल के प्रति आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक व मानसिक दृढ़ता के साथ कौशल भी ज़रूरी है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे हार-जीत की सोच से आगे बढ़ते हुए खेल भावना के साथ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन एवं निरंतर प्रेरणा से भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। खेलों को ग्रामीण स्तर तक बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेलों के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यपाल ने वियतनाम व पंजाब के मुक्केबाजों के मध्य आयोजित बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला मैच भी देखा। उन्होंने पंजाब टीम के विजेता लवप्रीत सिंह को सम्मानित किया।

इस प्रतियोगिता में खेलो इंडिया के स्वर्ण पदक विजेता सक्षम ठाकुर सहित रूस, वियतनाम, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के मुक्केबाजों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर हिमाचल पुलिस ऑरकेस्ट्रा 'हॉर्मनी ऑफ दि पाइन्स' ने देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर लोक निर्माण व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए आधुनिक हिमाचल के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

इस अवसर पर सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक इंद्र दत्त लखनपाल तथा हरीश जनारथा, नगर निगम की उप-महापौर उमा कौशल, प्रो बॉक्सिंग संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहिन्द्र सिंह सतान, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने योग को दैनिक जीवनचर्या में अपनाने पर दिया बल

राजभवन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

शिमला/शैल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन शिमला

में आयुष विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति के समग्र विकास में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्यपाल ने दैनिक जीवन में योग और प्राणायाम की परिवर्तनकारी बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध योग की विरासत को प्रदर्शित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना और पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम का अभ्यास हमें तनाव मुक्त जीवन जीने और स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. अर्पिता नेगी और आयुष विभाग की डॉ. मीना गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और योग विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ यौगिक क्रियाएं कीं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। राजभवन शिमला योग की परिवर्तनकारी बदलावों को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा सहित राजभवन के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

सकारात्मक मानसिकता और सही क्षमता के साथ राष्ट्र के विकास में योगदान करें युवा: राज्यपाल

शिमला/शैल। युवा राष्ट्र के विकास का आधार हैं। युवाओं की

ऊर्जा व प्रतिभा को सही दिशा व मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापकों व अभिभावकों की अहम भूमिका है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के सेंट थॉमस स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिम ड्रोन तथा श्याता ई. कॉमर्स ऐप लॉन्च के अवसर पर यह विचार प्रकट किए।

उन्होंने कहा कि सेंट थॉमस स्कूल के छात्र शयान अब्दुल जीशान द्वारा हिम ड्रोन निर्मित करने में सफलता प्राप्त करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और स्कूल की प्रधानाचार्या विधुप्रिया चक्रवर्ती, विद्यालय के अध्यापक व उनके अभिभावक भी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एजुकेशन एवं शिक्षा के वैश्विकरण से विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक मानसिकता और सही क्षमता के साथ युवा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शयान ने अपनी प्रतिभा को सकारात्मक रूप से प्रयोग कर हिम ड्रोन निर्मित किया जिसके लिए उन्हें एशिया के युवा उद्यमी के रूप में नवाज़ा गया है। कम लागत से निर्मित इस ड्रोन से अन्य विद्यार्थी भी प्रेरणा प्राप्त कर आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त श्याता ई-कॉमर्स ऐप द्वारा उड़ीसा रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के सदस्यों की मदद के लिए तत्पर है।

शुक्ल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जिसे शयान जैसे युवा साकार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा से भरी एक नदी के समान हैं जिसके प्रवाह को एक सही दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए अवसर व मंच प्रदान करने पर बल दिया ताकि वे सकारात्मक सोच के साथ समृद्ध, उन्नत व प्रगतिशील समाज निर्माण में अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकें।

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के

ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सोलन की अधिष्ठात्री देवी माँ शूलिनी के नाम पर आयोजित यह मेला धार्मिक आस्था का केन्द्र हैं। उन्होंने कहा कि यह मेला राज्य की समृद्ध संस्कृति के साथ-साथ उच्च परंपराओं का भी पोषण करता है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम देवी-देवताओं के नाम पर हैं, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 'हमारी संस्कृति, परंपराएं और कार्य देवी-देवताओं पर केंद्रित हैं। ये विश्वास ही हमें सकारात्मकता और आगे बढ़ने की ताकत देता है।

उन्होंने मेले के सुचारु आयोजन के लिए माता शूलिनी मेला आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न सामाजिक मुद्दों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उपायुक्त एवं माँ शूलिनी मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल को हिमाचली शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया।

राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया।

इससे पहले, राज्यपाल ने माँ शूलिनी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर पूनम ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने 10वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरूध अंतरराष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 10वीं एचपी पुलिस हाफ मैराथन-2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 10वीं हाफ मैराथन के माध्यम से नशे की बुराई के विरूध समाज के प्रत्येक वर्ग ने भारी बारिश के बावजूद जिस उत्साह का प्रदर्शन किया। वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशे की बुराई का संदेश लेकर इस दौड़ में बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग लोगों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि 'रन फार ड्रग फ्री, सेफ एंड ग्रीन हिमाचल' के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने में पुलिस विभाग का यह प्रयास निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। उन्होंने इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को इस तरह के जागरूकता अभियानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तभी समाज से नशे की बुराई को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। उन्होंने लोगों से हिमाचल को नशामुक्त बनाने में योगदान देने और नशे के विरूध हर अभियान में सहयोग का आहवान किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर कार्यकारी पुलिस महा निदेशक, सतवंत अटवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया और 10वी हाफ मैराथन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने माँ शूलिनी मेले को राष्ट्र स्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेले का शुभारम्भ किया। प्रदेशवासियों को मेले की बधाई

देते हुए मुख्यमंत्री ने माँ शूलिनी मेले को अगले वर्ष से राष्ट्र स्तरीय मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां के लोगों की देवी-देवताओं में गहरी आस्था है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इसमें समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना की गई है और यह आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक भी पेश करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार अगले चार वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और दो से तीन वर्ष के भीतर सरकार की कल्याणकारी नीतियां धरातल पर उतरेंगी।

मुख्यमंत्री ने शूलिनी माता की पूजा-अर्चना कर उन्हें नमन किया और राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने माँ शूलिनी मंदिर की वेबसाइट भी लॉन्च की और स्मारिका का विमोचन किया।

इससे पहले, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में 3.15 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री के सोलन आगमन पर लोग भारी उत्साह के साथ उनकी एक झलक पाने के लिए सोलन माल रोड पर एकत्रित हुए। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली।

उपायुक्त एवं माँ शूलिनी मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री को हिमाचली शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया। पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक जस्सी गिल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार और संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी और सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, सोलन नगर निगम की महापौर पूनम ग्रोवर, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश में 250 आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किये जायेंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश के लोगों को बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है। स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार प्रदेश में प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को विस्तृत स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में 250 आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किये जायेंगे, ताकि प्रदेश के लोग भारतीय चिकित्सा विज्ञान की इस पद्धति से लाभान्वित हो सकें। इन केंद्रों में अलग-अलग पैकेज के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसके अलावा, राज्य के विभिन्न भागों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा और वन विभाग के सहयोग से 500 से अधिक नए हर्बल गार्डन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उद्यान न केवल गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उत्पादन करेंगे, बल्कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का अतिरिक्त केन्द्र बनकर उभरेंगे।

वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए आयुष कार्यबल, उपचार प्रणालियों और सिद्धांतों का उपयोग करके आयुष को चिकित्सा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिली और स्थानीय स्वास्थ्य पद्धतियों को पुनर्जीवित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किसानों को औषधीय पौधों के क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को कृषि आधारित आर्थिकी को बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। भारत में कुछ आयुर्वेदिक औषधीय पौधों और मसालों का उपयोग कई प्रकार की सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार में सदियों से किया जाता है। ऐसे में सरकार के यह प्रयास निश्चित तौर पर सुलभ चिकित्सा के नए द्वार खोलेंगे।

चुनौतियां से निपटने और विकास में तकनीकी सहयोग करे आईआईटी मंडी:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईआईटी मंडी (कमांद) में कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में सहयोग देने और सरकार के

समक्ष पेश आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी मंडी तकनीकि सहयोग करे। उन्होंने कहा कि संस्थान की अपनी एक प्रतिष्ठा है और इसके द्वारा इजाद जा रही विभिन्न तकनीक समाज के कल्याण के लिए उपयोगी साबित होंगी। उपमुख्यमंत्री ने संस्थान में आज स्किल इंडिया जी 20 और एस 20 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उक्त बातें अपने संबोधन में कही।

उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया धरातल पर उम्मीद के मुताबिक नजर आना चाहिए ताकि युवाओं का रोजगार सुनिश्चित हो और देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने संस्थान के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी समय में विभिन्न प्रकार की तकनीक के लिए प्रदेश सरकार को प्रदेश के बाहर स्थित आईआईटी संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने ड्रोन तकनीक, रोबोटिक तकनीक आदि से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की समस्याएं दूर करने के लिए संस्थान से सहयोग भी मांगा।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास के मामले में देश में चीन से प्रतिस्पर्धा करने लायक अधोसंरचना और मानव संसाधन तैयार होना चाहिए ताकि देश को मजबूती प्रदान की जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान से समन्वय कर शिक्षित बेरोजगार और आम आदमी को स्किल प्रदान कर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए खाका तैयार किया जाएगा। मामले पर संस्थान से प्रारंभिक वार्तालाप पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कार्यक्रम के अवसर पर रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।

उपमुख्यमंत्री ने पेयजल पाइप लाइन में लीकेज और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संस्थान के सहयोग की अपील की। उन्होंने संस्थान को मंडी के कमांद में स्थापित करने के लिए कांग्रेस नेता ठाकुर कौल सिंह के प्रयासों का जिक्र भी किया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, निदेशक आईआईटी मंडी प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

पथ परिवहन निगम कर्मचारी महासंघ (इंटक) ने उपमुख्यमंत्री के मंडी दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री को कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई कि उपमुख्यमंत्री के साथ 18 मई 2023 को हुई कर्मचारियों की बैठक के दौरान पेश की गई वेतन विसंगति, वेतन पेंशन का भुगतान सहित अन्य मांगों पर उपमुख्यमंत्री द्वारा जल्द उचित विचार किया जाएगा। संघ के विभिन्न पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।

छह दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा हुआ बेली ब्रिज का निर्माण:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला और ठियोग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर छह दिनों की रिकॉर्ड समयावधि में बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि ठियोग के पास भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग का एक

बड़ा हिस्सा धंस गया था जिस कारण आने-जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि वे स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गए थे और विभाग को जल्द ही यहां अस्थाई पुल निर्मित करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि विभाग ने रिकॉर्ड समय के भीतर यह बेली ब्रिज तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर यातायात बहाल कर दिया है। इससे एक बार पुन: यह स्थापित हुआ है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जो कहती है उसे पूरा करने में विश्वास रखती है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क के धंसते हिस्से को स्थिर करने और इस बाधा के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर रिटेनिंग वॉल का निर्माण करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने पुल का औपचारिक उद्घाटन भी किया और एक सप्ताह के भीतर इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रयासों की सराहना की।

आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अन्तर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन प्रशिक्षकों को राहत प्रदान करने की दिशा में तेजी से कारवाई की है। उन्होंने कहा कि संघ की एक मुख्य मांग पूरी करते हुए सरकार ने उन्हें 20 दिनों के सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हें 'ऑन जॉब ट्रेनिंग' से पहले अथवा बाद में इन 20 दिनों के अवकाश का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

हालांकि, शेष अवकाश अवधि के दौरान, व्यवसायिक प्रशिक्षकों को या तो 'ऑन जॉब ट्रेनिंग' करनी होती है या अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए स्कूलों में उपस्थित रहना होता है। व्यवसायिक प्रशिक्षकों को देय अवकाश की अन्य पात्रता अप्रभावित रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ की अन्य मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने छह माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और 1 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जारी किया गया है।

प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमे सबसे नम्र है।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

राष्ट्र हित में आवश्यक है विपक्षी एकता

विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं। पटना के बाद दूसरी बैठक शिमला में होना प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि अधिकांश दल एकता की आवश्यकता को समझते हुये इन प्रयासों को असफल नहीं होने देंगे। क्योंकि अधिकांश दल अपने – अपने राज्यों से बाहर ज्यादा नहीं है। राज्यों में जिस तरह से केन्द्रीय जांच एजैन्सियों ने इन दलों के नेताओं के खिलाफ जांच का ताना – बाना खड़ा किया है उससे यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सारा विपक्ष एकदम भ्रष्ट है। केन्द्रीय एजैन्सियों की सक्रियता का मुद्दा विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय तक भी ले गया था। सत्रह विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। आज आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जेल में रह चुके हैं। इस तरह इन विपक्षी दलों के साथ जो कुछ व्यवहारिक रूप से घटा है उसने इनको यह एहसास करवाया है कि मोदी सत्ता का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए एकजुट होना आवश्यक है। लेकिन क्या यह दल कांग्रेस के बिना मोदी सत्ता को हरा सकते हैं शायद नहीं। क्योंकि अपने – अपने राज्यों में यह दल 2014 और 2019 में भी मोदी को नहीं हरा पाये हैं तब तो केन्द्रीय जांच एजैन्सियों का भी कोई बड़ा दखल इनके खिलाफ नहीं था। इसलिये आज की परिस्थितियों में कांग्रेस से ज्यादा इन दलों की आवश्यकता बन चुका है मोदी सत्ता को हराना। ऐसे में विपक्षी एकता की आवश्यकता के साथ ही इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना जरूरी है कि इस एकता का स्वरूप कैसा हो। इस स्वरूप पर विचार करने से पहले मोदी शासन के नौ वर्षों में जो कुछ घटा है उस पर नजर डालना आवश्यक है।

मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के पंद्रह वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ की अनुमति सहमति से ही सक्रिय राजनीति में आये हैं। संघ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि संघ भारत को हिन्दू राष्ट्र मानता और धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर नहीं है। उसकी नजर में गैर हिन्दू देश के प्रथम नागरिक नहीं हो सकते। श्रेष्ठ को ही सत्ता का अधिकार है और उसमें भी चयन के स्थान पर मनोनयन होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भामाशाही की अवधारणा की तर्ज पर प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिये। संघ की इस विचारधारा का परिचय उस कथित भारतीय संविधान से मिल जाता है जो डॉ. मोहन भागवत के नाम से वायरल होकर सामने आया है। इसी विचारधारा का परिणाम है कि भाजपा शासित राज्यों में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। आज भाजपा किसी भी मुस्लिम को विधानसभा या लोकसभा के लिये अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है। इस सोच का परिणाम है कि इन नौ वर्षों में कुछ लोगों के हाथों में देश की अधिकांश संपत्ति केन्द्रित हो गयी है। भारत बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुभाषी देश है। मुस्लिम देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। इस जनसंख्या को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखना क्या व्यवहारिक और संभव हो सकता है शायद नहीं। लोकतन्त्र में मतभेद आवश्यक है। लोकतन्त्र में सत्ता से तीखे सवाल पूछना आवश्यक है।

लेकिन आज सत्ता से मतभेद अपराध बन गया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर किस तरह एक मुस्लिम पत्रकार को भाजपा के आईटी सैल ने ट्रोल किया है उसकी कड़ी निन्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन को करनी पड़ी है। इस तरह भारत में लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने के जो आरोप लग रहे हैं वह स्वत: ही प्रमाणित हो जाते हैं। इसी के साथ इन नौ वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी जिस चरम पर पहुंची है उससे भी आम आदमी त्रस्त हो चुका है। इन्हीं सारी परिस्थितियों ने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। कांग्रेस नेतृत्व लगातार सत्ता से लड़ता आ रहा है और आज राहुल गांधी से सत्ता डरने लग गयी है। इसी डर के कारण राहुल की सांसदी छीनी गयी है। इसलिये इन नौ वर्षों में जो कुछ घटा है और उसमें जिस तरह कांग्रेस सत्ता के सामने खड़ी रही है उसको सामने रखते हुये आज विपक्षी एकता में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका दे दी जानी चाहिये। वैसे तो जो दल अपना राष्ट्रीय दर्जा खो चुके हैं उन्हें इस समय राष्ट्रहित में कांग्रेस में विलय कर जाना चाहिये।

निराधार है अमेरिकी रिपोर्ट, आधुनिक भारत के निर्माण में ईसाइयों का है महत्वपूर्ण योगदान

गौतम चौधरी

भारत दुनिया का वह देश है जहां सांस्कृतिक विविधता फलती – फूलती है और कई धर्मावलंबी सह – अस्तित्व के साथ निवास करते हैं। ईसाई धर्म को राष्ट्र के जीवंत टेपेस्ट्री में बुने गए एक आवश्यक धागे के रूप में देखा जाता है। सभी भारतीय अपनी धार्मिक संबद्धता के बावजूद, भारतीय उत्सव और आपसी सम्मान की भावना के साथ यह स्वीकार करते है कि सभी धर्मो को देश के कानूनों और मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाता है। यह सांस्कृतिक समन्वय शांति, सद्भाव और विविध धार्मिक विश्वासों के सह – अस्तित्व को बढ़ावा देती है और अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए गए आरोपों का खंडन करती है। उस निपोर्ट में कहा गया है की भारत में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। यह जानते हुए कि ईसाई धर्म का व्यक्तियों और समुदायों पर समान रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अलग – अलग घटनाओं और भारत में ईसाई धर्म के व्यापक आख्यान के बीच विचार करना अत्यावश्यक हो जाता है।

आधुनिक युग में, भारत में ईसाई धर्म ने एक परिवर्तनकारी यात्र शुरू की है, जिसने देश के विकास पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। अल्पसंख्यक धर्म होने के बावजूद, ईसाइयों को विभिन्न चरणों में राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने विभिन्न क्षेत्रें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस धर्म ने अपने प्रचारकों के माध्यम से भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुधारों के परिदृश्य को आकार मिला है। अमेरिकी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के विपरीत, ईसाई मिशनरियों को विशेष रूप से भारत में शैक्षिक प्रगति के उनके प्रयास में राज्य द्वारा सहायता प्रदान की गई है। राज्य द्वारा प्रदान की गई रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस पर ईसाइयों ने अक्सर देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखते हुए कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की है। इन संस्थानों ने न केवल अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया है बल्कि स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय भाषाओं को ऊपर उठाया है और भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया है। 1540 में पांसिस्कन द्वारा स्थापित गोवा में सांता फे स्कूल, यूरोप के बाहर पहला औपचारिक ईसाई शैक्षिक का केन्द्र है, जो आज भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अन्य प्रमुख ईसाई कॉलेज जैसे कोलकाता में सेंट जेवियर्स कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मसूलीपटनम में राबर्ट टी. नोबल कॉलेज, नागपुर में हिस्लोप कॉलेज और आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज। ये तमाम शैक्षणिक संस्थाएं उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरे हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऐसे संस्थान राज्य द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रावधानों की मदद से ही अपने आप को प्रभावशाली बना पाए हैं। अस्पतालों, औषधालयों और देखभाल केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, उन्होंने जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। विशेष रूप से, ईसाई स्वास्थ्य देखभाल संगठनों ने देखभाल, सहायता के माध्यम से एचआईवी/एड्स जैसी समस्याओं से लोगों को उबारने में मदद की है।

उत्तर – पूर्वी राज्यों, जहां ईसाइयों की संख्या ज्यादा है वहां भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 371 लगाया गया है। यह इन राज्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसके कारण कई मिशनरियां यहां अपना काम आसानी से कर रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष संवैधानिक प्रावधानों ने तेजी से बदलती दुनिया के बीच उनके संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए आदिवासी रीति – रिवाजों, परंपराओं, भूमि अधिकारों और आधुनिकीकरण को और सुरक्षित किया है। उत्तर – पूर्व भारत के लोग ईसाई धर्म के इस पहलू को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इसने उन्हें नए क्षितिज को अपनाने के साथ – साथ अपनी जड़ों से जुड़ने में सहायता प्रदान की है। ईसाई धर्म ने भारत के उत्तर – पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के बीच एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। मिशनरी शिक्षा शुरू करने, निरक्षरता का मुकाबला करने और सामाजिक – आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। उन्होंने लिखित भाषाओं की शुरुआत और स्वदेशी ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागालैंड, एक सांस्कृतिक स्वर्ग है, जिसे ईसाई राज्य धार्मिक रूप से कहा जाता है क्योंकि इसकी 80 प्रतिशत से अधिक आबादी खुद को ईसाई मानता है। राज्य में लगभग 1,708 बड़े चर्चा हैं। नागालैंड, जिसमें कथित तौर पर दुनिया में बैपटिस्ट ईसाइयों का सबसे बड़ा समुदाय निवास करता है। यह भारतीय वहुलतावाद का एक आदर्श उदाहरण है। इससे यह साबित होता है कि भारत को ईसाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क के रूप में वर्णित कर अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने पूर्वाग्रह का परिचय दिया है।

ईसाइयों द्वारा अपने विश्वास का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सरकार का समर्थन, भारतीय समाज की समावेशी प्रकृति को प्रमाणित करता है। दुर्लभ घटनाओं के बावजूद जो भारत में ईसाई धर्म की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर सकती हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे पूरी ईसाई आबादी या देश की मुख्य भावना को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसके अलावा, भारत में अल्पसंख्यक अपनी और अपने अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसके लिए विदेशी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वे अपनी चिंताओं को व्यद्र करने के लिए शक्तिशाली हैं क्योंकि संविधान ने उनके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। भारतीय अल्पसंख्यकों का नायक कोई बाहरी शक्ति नहीं हो सकता है। भारत के अल्पसंख्यक विशुध रूप से भारतीय हैं और भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की आख्या भारत को बदनाम करने वाला दिखता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 'खादी योगा मैट' किया गया लॉन्च

शिमला। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 के शुभ अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के चेयरमैन मनोज कुमार ने मुंबई स्थित केवीआईसी मुख्यालय में 'खादी योगा मैट' को लॉन्च किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' दिन प्रति दिन नये मानदंड स्थापित कर रहा है। 'खादी योगा मैट' को लॉन्च करना भी इसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि यह योग चटाई पूरी तरह से घरेलू और पर्यावरण के अनुकूल है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि सभी तरह के योगासन इस पर किये जा सकते हैं।

इस अवसर पर केवीआईसी चेयरमैन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पश्चिमी क्षेत्र के 237 लाभार्थियों के लिये करीब 25 करोड़ रूपये का मार्जिन राशि अनुदान जारी किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2022 – 23 में 1.34 लाख करोड़ रूपये का एतिहासिक कारोबार होने पर देश के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लाखों खादी कारीगरों और केवीआईसी अधिकारियों को बधाई दी।

मनोज कुमार ने 'खादी योगा मैट' जारी करने से पहले केवीआईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में योग और प्रणायाम किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ही प्रयास था जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव किया जिसे तीन महीने की अवधि में ही स्वीकार कर लिया गया और 21 जून, 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से भारत योग गुरू के रूप में आज दुनिया को योग का पाठ पढ़ा रहा है।

केवीआईसी चेयरमैन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवीआईसी ने ''वोकल फार लोकल'' (स्थानीय उत्पाद के लिये मुखर) और ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान अवधारणा को नई उंचाईयों पर पहुंचाया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केवीआईसी उत्पादों का बिक्री कारोबार 1.34 लाख करोड़ रूपये के पार पहुंचा जबकि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में 9,54,899 रोजगार के नये अवसर सृजित किये गये। उन्होंने कहा कि आज लांच 'खादी योगा मैट' पूरी तरह से घरेलू उत्पाद है जिसे खादी कारीगरों के कौशल से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस नये घरेलू उत्पाद के लिये मुखर होना चाहिये और जब हम सभी स्थानीय उत्पादों को लेकर मुखर होंगे तभी हमारे उत्पाद स्थानीय से वैश्विक उत्पादों की श्रेणी में पहुंचेंगे।

केवीआईसी की एतिहासिक सफलता को दोहराते हुये उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अभियान के साथ पीएमईजीपी ने देश के युवाओं को साथ लाने में नया रिकार्ड स्थापित किया है। इस योजना के साथ 'रोजगार पाने के बजाय रोजगार प्रदाता बनने' का सपना जुड़ा हुआ है।

हिम गंगा योजना: दूध आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

प्रथम चरण के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

शिमला। हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधाव अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के पुरस्कार विजेताओं की सूचीषि प्रधान राज्य है। कृषि और संबद्ध गतिविधियां प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 70 प्रतिशत को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 13.62 प्रतिशत है। पशुपालन भी कृषि संबंधी गतिविधियों का अभिन्न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रें में पशुपालन और डेयरी गतिविधियां प्रमुखता से की जाती रही हैं। प्रदेश में पारम्परिक पद्धति के साथ – साथ नई पहल से पशुपालन के फलस्वरूप हिमाचल में संपन्न पशुधन है। 19वी पशुधन जनगणना के अनुसार, हिमाचल में पशुधन की कुल संख्या 48,44,431 है। इनमें 21,49,259 गाय, 7,16,016 भैंस शामिल हैं। इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़े और मुगयां इत्यादि अन्य पशुधन भी ग्रामीण आर्थिकी को संबल प्रदान करते हैं।

राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविदर सिह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने एक नई योजना हिम – गंगा की घोषणा की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को लागत आधारित दूध का सही मूल्य प्रदान किया जाएगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अपने पहले बजट में हिम – गंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण वर्ष 2023 – 24के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महिलाओं से जुड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं की पहचान कर उन्हें भी संगठित किया जाएगा।

इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके उपरान्त चरणबद्ध ढंग से इस योजना को अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा जिला कांगड़ा में 150 और जिला हमीरपुर में 50 दुग्ध आधारित समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले छह माह के दौरान लगभग 48 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं।

हिमाचल में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने और दुग्ध संबंधी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जिला कांगड़ा के डगवार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के सहयोग से लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियां एनडीडीबी की सहायता से की जाएंगी। एनडीडीबी संयंत्र के संचालन और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए अपने खर्च पर दो सलाहकार भी उपलब्ध करवाएगा। लगभग तीन लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पूर्ण स्वचालित डगवार दुग्ध संयंत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इस संयंत्र के स्थापित होने से जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चम्बा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे।

इसके अतिरिक्त एनडीडीबी से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पाऊडर संयंत्र स्थापित करने के साथ ही 11 संयंत्रें के उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने प्रतिज्ञा पत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने के लिए किए गए वायदे को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। हिमगंगा योजना के शुभारंभ से प्रदेश सरकार इस वायदे को पूरा करने की ओर अग्रसर है।

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच

शिमला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम – किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई – केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई – केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई – केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई – केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों हेतु ई – केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।

कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम – किसान के काम तो आएगा ही और किसानों को कभी भी कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी।

तोमर ने कहा कि पीएम – किसान एक अभिनव योजना है जिसका लाभ बिना किसी बिचौलियों के केंद्र सरकार किसानों को दे पा रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को टेक्नालॉजी की मदद से ही लाभ देना संभव हो पाया है। इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है जो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार ने टेक्नालॉजी का उपयोग करके यह जो ऐप बनाया है उससे काम काफी सरल हो गया है। भारत सरकार ने सभी आवश्यक सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध करा दी हैं, अब राज्य ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो सभी हितग्राहियों तक हम पहुंच जाएंगे और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह आग्रह करते रहे हैं कि योजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है तो हम सेचुरेशन पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है जिसे शीघ्र पूर्ण करने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पात्र किसानों को योजना की 14वीं किस्त मिल सकेंगी। तोमर ने अनुरोध किया कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें प्रवृत्त हों।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टेक्नालॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने भी अपने विचार रखें। अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा ने ऐप की विशेषताएं बताई। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने योजना व ऐप के लाभ से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं के जरिये भी ऐप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें सहायक युवाओं को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रु., 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं जिनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोविड के समय लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक मजबूत साथी साबित हुई थी। योजना ने किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया व कठिन समय में आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन व बैंक खाता विवरण अपडेशन से संबंधित कठिनाइयों का डिजिटल पब्लिक गुड्स के प्रभावी उपयोग से समाधान हो गया।

पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिये सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने – आप में एक कीर्तिमान है। नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ऐप किसानों को योजना व पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत – सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो यूजर स्टेटस माडयूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने व ई – केवाईसी का स्टेटस जान सकते है। विभाग ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्राम – स्तरीय ई – केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है।

अनछुए पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल दे रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला शहर आज भी पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है। देश-विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इनकी बढ़ती संख्या के अनुरूप शहर में सड़क अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ पर्यटकों एवं आंगतुकों को आवाजाही की निर्बाध सुविधा प्रदान करना है।

इस योजना के तहत आवंटित धनराशि में से लगभग 77 करोड़ रुपये भूमि एवं निजी ढांचागत निर्माणों इत्यादि के अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 20 करोड़ रुपये का प्रावधान सड़कों के विकास और विस्तारीकरण के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, मेट्रोपोल से प्रदेश उच्च न्यायालय जंक्शन तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस कार्य में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व-विख्यात पर्यटन स्थल शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को सुविधाएं प्रदान करने पर प्रदेश सरकार विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में सर्वेक्षण करने तथा संकरे एवं तंग स्थलों की पहचान कर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है और आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पार्किंग स्थल भी विकसित किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत बदलावों एवं पर्यटन मित्र दृष्टिकोण से कार्य कर रही है साथ ही, पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में भी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कांगड़ा घाटी को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न सुविधाओं का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि मई, 2023 तक प्रदेश में लगभग 72 लाख पर्यटक पहुंचे और प्रदेश सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में पर्यटकों की इस संख्या को पांच करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार एक नई पर्यटन नीति भी लाएगी जिससे पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।

हिम उन्नति के तहत प्रदेश में लगभग 2600 क्लस्टर विकसित किये जायेंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्रों के पुर्नद्धार के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। प्रदेश की ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में कृषि का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्षेत्र-विशेष आधारित एकीकृत और समग्र कृषि विकास योजना 'हिम उन्नति' शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 'हिम उन्नति' राज्य में कृषि को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार की गई है। यह एक क्षेत्र-आधारित तथा क्लस्टर-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित समग्र विकास योजना है, जिससे लक्षित एवं एकीकृत कृषि विकास सुनिश्चित होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेशभर में चिन्हित किए गए समूहों के लिए स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और मिट्टी की स्थिति अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी।

कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का समन्वय और जाइका चरण-2 की उप-परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 'हिम उन्नति' का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। योजना के अन्तर्गत प्रारंभिक चरण में दुग्ध उत्पादन, दालें, बाजरा, सब्जियां, फल, फूल, नकदी फसलें और प्राकृतिक खेती में विशेषज्ञता वाले समूहों के लिए 150 करोड़ रुपये का रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में राज्य में कुल 2600 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष, कृषि विभाग ने खरीफ मौसम में 51 क्लस्टर निर्धारित किए हैं और इसी वर्ष रबी सीजन के दौरान लगभग 286 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

हिमाचल को 'फल राज्य' के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्द्धन (एचपी-शिवा) परियोजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की प्रचुर कृषि-जलवायु स्थितियों का दोहन करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले राज्य के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 28 विकास खंडों में 6,000 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1030 करोड़ रुपये एशियन विकास बैंक और 262 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

इस परियोजना के अन्तर्गत 'एक फसल एक क्लस्टर' के दृष्टिकोण से संतरे, अमरूद, अनार और कई अन्य फलों का उत्पादन किया जाएगा। इसमें निजी भूमि मालिकों को भी इन फलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, मज़बूत मूल्य श्रृंखला बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से फसल उपरांत नुकसान को कम करते हुए फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना से लगभग 15 हजार किसान-बागवान प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होंगे।

परियोजना के तहत 'बीज से बाजार' अवधारणा को आधार बनाकर किसानों के उत्पादों की वैज्ञानिक तरीके से गुणवत्ता बढ़ाकर उन्हें उचित बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 14 चिन्हित फलों और फसलों की बाजार मांग और उनकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का अध्ययन भी किया जाएगा।

आपदा से संबंधित सटीक सूचना उपलब्ध करवाएगा 'सचेत' ऐपः ओंकार चंद शर्मा

शिमला/शैल। आगामी बरसात के मौसम के दौरान आपदा प्रबन्धन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव राजस्व, ओंकार चंद शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि तैयारियों के अभाव अथवा कारवाई में देरी से एक भी बहुमूल्य जीवन न खोने देने की दृष्टि से आपदा प्रबन्धन

प्रकोष्ठ समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है।

बैठक में बांधों एवं जलाशयों में जल स्तर, भूकंप, बादल फटने, बिजली गिरने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की समयपरक सूचना उपलब्ध करवाने पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि यह बहुमूल्य मानव जीवन सहित अमूल्य संपदा की रक्षा में यह सहायक होता है।

प्रधान सचिव ने आधुनिक दौर की प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 'सचेत' ऐप विकसित किया गया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर आपदा से संबंधित सटीक सूचना नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाती है। इस ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी एवं चेतावनियां समय पर उपलब्ध होती हैं और किसी स्थान विशेष में आपदा के समय क्या करें अथवा न करें, इसके बारे में भी यह हमें निर्देशित करता है।

उन्होंने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को बांधों, विद्युत परियोजनाओं और नदी प्रबन्धन प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव, भूस्खलन और बांधों से पानी छोड़ने संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के निर्देश भी दिए ताकि प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए प्रतिक्रिया दलों को समय पर तैयारी कर कारवाई के लिए सचेत किया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष तौर पर नदी तटों पर इस तरह की गतिविधियों से क्षरण के कारण सड़कों को क्षति एवं भूस्खलन से दुर्घटनाएं इत्यादि सामने आती हैं। ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि बरसात के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुलों एवं सड़कों के टूटने, पेयजल आपूर्ति योजनाओं के बहने, पेयजल आपूर्ति पाईपों तथा विद्युत आपूर्ति तारों एवं खम्बों के टूटने से परिवहन सेवाओं, पेयजल व विद्युत आपूर्ति इत्यादि में बाधा पहुंचती है। उन्होंने संबंधित विभागों को ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए समय पर एवं त्वरित कारवाई करते हुए हानि को न्यून करने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़कों के किनारे एवं अन्य नालियों को साफ रखने तथा खतरा संभावित क्षेत्रों में मशीनों, आधुनिक उपकरणों एवं मानव संपदा की समुचित तैनाती के भी निर्देश दिए।

बैठक में यह भी कहा गया कि राज्य में स्थित छोटे बांधों को बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के अन्तर्गत लाया जाए और भविष्य में निर्मित होने वाले बांधों को भी इस अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्मित किया जाए।

प्रधान सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, गृह रक्षक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अतिरिक्त राज्य में आपदा अथवा अन्य आपात स्थिति में राहत एवं बचाव के लिए 15 हजार 'आपदा मित्र' एवं राज्य स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के दृष्टिगत प्रदेशभर में आवश्यक उपकरणों के साथ चेतावनी दलों समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित बलों की समुचित उपलब्धता के दृष्टिगत इन आपदा मित्र एवं अन्य स्वयंसेवकों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के समन्वय से पाठशालाओं और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कार्यक्रमों और मॉकड्रिल का आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही तैयारियों का भी जायज़ा लिया जा सके।

ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि प्रभावितों एवं ज़रूरतमंदों को समय पर सहायता, अनुदान एवं राहत निधि आवंटित करने में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आपात स्थिति के दृष्टिगत आपदा संभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों, कंबल, स्लीपिंग बैग, जल भण्डारण टैंकों और फॉगिंग मशीनों का समय रहते समुचित प्रबन्धन एवं भण्डारण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला उपायुक्तों को वित्तीय मामलों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली में प्रविष्टियां दर्ज करने और निरंतर डाटा अद्यतन करने के भी निर्देश दिए गए।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को प्रदेश में सुरक्षित यात्रा के लिए परामर्श जारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हो रही बारिश के दृष्टिगत पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को प्रदेश में सुरक्षित यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, आर.एस. बाली ने जारी एक वक्तव्य में कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को विभाग की ओर से सलाह दी गयी है कि वे यात्रा करते समय अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन हमेशा ऑन रखें तथा मौसम की पूर्व जानकारी के अनुसार ही यात्रा आरम्भ करें। यह भी सलाह दी गयी है कि वे केवल निर्देशित मार्गों पर ही यात्रा करें तथा इधर-उधर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि भारी धुंध के कारण कई बार दृश्यता कम हो जाती है और ऐसे में यात्रा के दौरान गाड़ी धीमी गति से चलाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को लापरवाही व तीव्र गति से गाड़ी चलाने से बचना चाहिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों की स्थितियों के अनुसार उन्हें धीमी गति से वाहन चलाते हुए अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए।

बाली ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से मनाली-कीरतपुर फोरलेन सड़क पर मंडी से पंडोह के बीच भूस्खलन के कारण यातायात अवरूद्ध होने की कुछ अपुष्ट सूचनाएं वायरल की जा रही हैं। हालांकि, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम के दौरान सड़कों के निर्माण और चौड़ा करने के कारण ऐसी प्राकृतिक घटनाएं सामान्य हैं।

उन्होंने कहा कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार मलबा हटाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और कुल्लू पहुंचने के लिए यातायात को चैलचौक-गोहर मार्ग पर भी मोड़ा गया है जिस कारण यातायात की गति थोड़ी धीमी है। इसके अलावा कुल्लू की ओर से आने वाले वाहनों के लिए कमांद (कांडी-कटोला) मार्ग भी खुला है और इसे वन वे किया गया है। ऐसे में पर्यटक वाहन लंबे समय तक फंसे नहीं रहेंगे जैसी कि सूचनाएं वायरल की जा रही हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वह झूठी व अपुष्ट सूचना फैलाने वालों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय तथा बाजार इत्यादि खुले हैं और लोग सामान्य तौर पर अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हल्के वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी जा रही है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और मशीनरी सड़क को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं जिससे जल्द ही सड़क को भारी और अन्य वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

जल विद्युत क्षेत्र के विकास से होगा अतिरिक्त राजस्व अर्जन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल को सोने की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में जल विद्युत दोहन की अपार क्षमता है और इसके उचित प्रबन्धन से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है। प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर लोगों की समृद्धि और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की जल संपदा का समुचित उपयोग करने पर विशेष बल दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी पूर्ति हेतु प्रदेश में पन बिजली विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार जल विद्युत क्षमता के पर्याप्त दोहन के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही एक खुली एवं आकर्षक नीति लेकर आएगी। राजस्व बढ़ाने के दृष्टिगत बिजली की बिक्री और खरीद के कुशल प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत सेल की स्थापना की जाएगी।

जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारक है। राजस्व सृजन, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में जल विद्युत क्षेत्र की महत्वपर्ण भूमिका है तथा इसका विकास अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त पनबिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है जिससे प्रदेश की परिचालन क्षमता लगभग 21,000 मेगावाट हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली उत्पादन के अलावा इसके वितरण और बिक्री पर विशेष ध्यान दे रही है। अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा निगम को अपने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं एवं राजस्व में बढ़ोतरी के दृष्टिगत निविदा प्रक्रिया की अवधि को कम करने के लिए भी कहा गया है ताकि राज्य के लोगों को लाभ मिल सके।

एचपीटीसीएल द्वारा 464 करोड़ रुपये से कालाअंब, बरशैनी, कांगू, पलचान, धर्मपुर और हिलिंग में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) उप-केन्द्र, पांच ट्रांसमिशन लाइनों और एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र का निर्माण पूरा किया जाएगा।

निगम के पास राज्य में 15 उप-केन्द्र और 964 किलोमीटर सर्किट लाइनें हैं जिनसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 166.99 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई। वर्ष 2025 में निगम की आय 455 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। निगम अगले 18 महीनों के भीतर छः किलोमीटर लंबी शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जोकि 450 मेगावाट की शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना जुलाई, 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

एचपीपीटीसीएल सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बल्क ड्रग पार्क जैसी परियोजनाओं की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा ऊना जिले के लमलेहड़ी और पेखुबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन व्यवस्था सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसे हासिल करने के लिए नेहरियां से ऊना तक 220/132 केवी उप-केन्द्र और 41 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा, सोलन जिले के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क और सिरमौर जिले के कालाअंब में औद्योगिक क्षेत्र की बिजली मांगों को पूरा करने के लिए निगम द्वारा उचित ट्रांसमिशन व्यवस्था की जाएगी।

सेब सीजन के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर्स में भंडारण दरें तय

शिमला/शैल। आगामी सेब सीजन-2023 के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर में सेब के भंडारण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं यह जानकारी एचपीएमसी के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए, सेब को स्वयं के डिब्बे अथवा क्रेट में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह रखने की दर निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो सेब उत्पादक एचपीएमसी द्वारा प्रदान किये गये डिब्बे एवं क्रेट्स का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दर 1.70 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य बेहतर भंडारण सुनिश्चित करते हुए बेहतर विकल्पों के साथ सेब उत्पादकों का समर्थन करना है।

सेब व्यापार में बेहतर योगदान के लिए पहचानी जाने वाली निजी कंपनियों और फर्मो को सेब को अपने खुद के डिब्बे या क्रेट्स में रखने की सुविधा 1.90 प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर पर मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग निगम के डिब्बे या क्रेट्स चुनते हैं, उनके लिए यह दर 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये दरें सेब की ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भंडारण सुविधाओं के मूल्य को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि भंडारण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि निगम के सभी सीए स्टोरों में सेब के भंडारण के लिए केवल क्रेट या डिब्बे का उपयोग किया जाये। उन्होंने कहा कि निगम के प्रयासों से सेब उत्पादकों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि निगम सेब उत्पादकों, निजी कंपनियों और फर्मो सहित सभी हितधारकों के लिए एक निष्पक्ष और लाभकारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है।

नौणी विवि में भूतपूर्व छात्रों के साथ रीकनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी द्वारा पूर्व छात्र रीकनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की संस्थागत विकास योजना (एन.ए.एच.ई.पी. आईडीपी) के तहत आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ को और अधिक गतिशील बनाने के बारे में चर्चा की। रीकनेक्ट कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था जिसमें पूर्व छात्र ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में शामिल हुए थे। देश के विभिन्न हिस्सों सहित अमेरिका और कनाडा से कई छात्र ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्वविद्यालय में आये भूतपूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सुविधाओं, विशेष रूप से पूर्व छात्र एंगेजमेंट केंद्र का दौरा करवाया गया।

डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉ. मनीष शर्मा ने पूर्व छात्रों का स्वागत किया और बताया कि विश्वविद्यालय पूर्व छात्रों के साथ विश्वविद्यालय से उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए इस तरह के रीकनेक्ट कार्यक्रम आयोजित करेगा। आईडीपी की प्रधान अन्वेषक डॉ. केके रैना ने छात्रों के समग्र विकास और पूर्व छात्रों के साथ जुड़ाव के लिए आईडीपी परियोजना के तहत की गई पहल के बारे में बात की। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष डॉ आरके ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय के विकास और वर्तमान से ऊंचे स्तर पर ले जाने में पूर्व छात्रों की बड़ी भूमिका है। अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने पूर्व छात्रों के कॉर्पस फंड और इसकी स्थापना के लिए तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों पर चर्चा की।

इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि यह कार्यक्रम नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक था, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय ने पूर्व छात्रों की आकांक्षाओं को मापने की योजना बनाई है और कैसे विश्वविद्यालय वर्तमान छात्रों और उद्योग के साथ जुड़ने के लिए एसोसिएशन के साथ काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पूर्व छात्रों के लिए इस संघ को और अधिक आकर्षक बनाने की प्रक्रिया में है।

सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए और कुछ ने अपने छात्र दिनों की यादें भी साझा की। प्रतिभागियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये और बताया कि वे एक कॉर्पस फंड के निर्माण में कैसे मदद कर सकते हैं। कई सदस्यों ने उपस्थित छात्रों को प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के लिये उद्योग जगत से जुड़कर काम करने की इच्छा व्यक्त की। एलुमिनाई मीट के आयोजन पर भी चर्चा हुई। वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ.सीएल ठाकुर ने कार्यक्रम में भाग लेने और अपनी राय साझा करने के लिए पूर्व छात्रों का धन्यवाद दिया।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस के नाम से जाना जाएगा आईटी विभाग

शिमला/शैल। डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन के बदलते समय के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसकी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश संभवतया भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसके विभाग को डिजिटल नामकरण प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार यह निर्णय राज्य को डिजिटल रूप से उन्नत और आधुनिक राज्य में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1999 में स्थापित हुआ था जिसका वर्ष 2002 में उद्योग विभाग में विलय कर दिया गया। वर्ष 2004 में उद्योग विभाग से विभाजित कर जैव-प्रौद्योगिकी के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इसका विलय कर दिया गया। 13 अप्रैल, 2007 को आईटी विभाग से जैव-प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अलग कर इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में लाया गया। हालांकि, बदलते समय के साथ विभाग द्वारा किए जा रहे कई कार्य अप्रचलित हो गये थे और कई नवीन बदलावों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि विभाग का विजन और मिशन स्टेटमेंट तैयार किया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के मद्देनजर, विभाग की भूमिका और जिम्मेदारियों में भी बदलाव देखने को मिला है और अब इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश देखने को मिल रहा है।

इस विभाग का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के विभागों का डिजिटलीकरण कर राज्य में प्रभावी शासन और समावेशी विकास के नए युग की स्थापना करना है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के अवसरों को देखते हुए, विभागों के चार मुख्य क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकी के दायरे में आएंगे। इनमें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डाटा गवर्नेंस, समावेशी विकास के लिए डिजिटल परिवर्तन और आईटी निवेश तथा उद्योग संवर्धन शामिल है। इनमें आगे डिजिटल प्रौद्योगिकी, टेली-संचार, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर-सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कृत्रिम मेधा, ड्रोन और ड्रोन-आधारित सेवाएं, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन और बिग डेटा एनालिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित करना और लागू करना शामिल है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए प्रभावी मानचित्रण, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी का एकीकरण और कार्यान्वयन, उभरती प्रौद्योगिकी सहित सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

संशोधित नियमों में राज्य डेटा सेंटर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सहित राज्य में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी, विकास, प्रबंधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नयन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

इसमें नागरिकों और सरकारी संगठनों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को लागू करने और अपग्रेड करने में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करना शामिल है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके।

डॉ. जैन ने कहा कि आईटी विभाग अब अपनी नई पहचान के तहत सभी हितधारकों को जोड़कर उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों से जोड़ेगा और प्रदेश के लोगों को भी डिजिटलीकरण के फायदों से जोड़ने के लिए अधिक पेशेवर तरीके से कार्य करेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मुख्य संसदीय सचिवों को अदालत के नोटिस तामील न हो पाना क्या अराजकता का प्रमाण नहीं है

- भाजपा विधायक भी याचिकाकर्ता है और नोटिस तामील न होने पर चुप है क्यों?
- इन नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उच्च न्यायालय में सरकार के अपने शपथ पत्र की अवहेलना हुई है।

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार में नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का संज्ञान लेते हुये सभी मुख्य संसदीय सचिवों को पार्टी बनाकर नोटिस जारी किया है। लेकिन मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस अभी तक तामील नहीं हो पाये है। नोटिस तामील न होने के कारण अदालत को अगली पेशी देनी पड़ती है। नोटिस की तामील ही न हो पाने पर आम आदमी यह आश्वस्त होता जा रहा है कि प्रदेश में सही में प्रशासनिक अराजकता का दौर चल रहा है। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों को राज्य सचिवालय में कार्यालय और स्टाफ दोनों मिले हुये हैं। यह लोग अपने इन कार्यालयों में बैठकर अपने कार्यो का निष्पादन करते हैं। अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी यह लोग सार्वजनिक कार्यो को बराबर अंजाम दे रहे हैं। यह लोग ऐसे नहीं हैं कि इन्हें उच्च न्यायालय के नोटिस सर्व करने में कोई व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती है। नोटिस तामील न हो पाना केवल प्रशासनिक अराजकता को ही प्रमाणित करता है।

मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर जब भी उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा उसका प्रदेश की राजनीति पर गंभीर असर पड़ेगा यह तय है। क्योंकि जब पूर्व में स्व.वीरभद्र सिंह के शासन में भी ऐसी ही नियुक्तियां हुई थी और उच्च न्यायालय में उन्हें हिमाचल प्रोटेक्शन फॉर्म के देश बंधु सूद ने चुनौती दी थी तब यह नियुक्तियां अदालत ने रद्द कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इसी के साथ एक्ट में कुछ संशोधन करके नया एक्ट पारित कर लिया गया। लेकिन इस एक्ट को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी। तब सरकार ने उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर यह कहा था कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता है वह फिर से ऐसी नियुक्तियां नहीं करेगी। इस शपथ पत्र के बाद आवश्यक हो जाता है कि ऐसी नियुक्तियां करने से पहले उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह लाया जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी जो एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी वह असम के मामले के साथ टैग हो गयी थी और उस पर जुलाई 2017 में फैसला आ गया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्य विधानसभा को इस आश्य का अधिनियम पारित करने का अधिकार ही नहीं है।

ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और प्रदेश सरकार के उच्च न्यायालय में अपने शपथ पत्र के बाद भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मंत्रिमण्डल के विस्तार से दो घंटे पहले क्यों की गयी? क्या उस समय पार्टी में भाजपा की सेंधमारी की आशंका हो गयी थी? या किसी अन्य मकसद के लिये हाईकमान पर दबाव बनाने के लिये यह नियुक्तियां की गयी थी? इन नियुक्तियों में सरकार के अपने ही शपथ पत्र की उल्लंघना की गयी है। उच्च न्यायालय सरकार के शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुये इन नियुक्तियों को अवैध घोषित करने के साथ ही नियुक्त हुये मुख्य संसदीय सचिवों को अयोग्य भी ठहरा सकता है इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में दायर हुई अंतिम याचिका भाजपा विधायकों की है। लेकिन इन लोगों ने इन मुख्य संसदीय सचिवों को उच्च न्यायालय के नोटिस की तामील न हो पाने पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आ रही है। जबकि नोटिस की तामील प्रशासनिक मामला है। ऐसे में यह सवाल उठने लगते हैं कि कहीं भाजपा नेतृत्व इस मामले में सरकार पर कोई दबाव तो नहीं बना रहा है। शायद इस अघोषित दबाव के कारण ही भाजपा काल के प्रशासन को ही यथास्थिति चलाया जा रहा है और भ्रष्टाचार के प्रति आंख बंद कर ली गयी है।

क्या प्रदेश भाजपा भी राजनीति के लिये धर्म को हथियार बना रही है?

मनोहर हत्याकाण्ड पर आयी प्रतिक्रियाओं से उभरी चर्चा

- कथित दोषी परिवार के खिलाफ लगाये गये अवैध कब्जे और खाते में दो करोड़ जमा होने की सच्चाई क्या है
- क्या कांग्रेस सरकार बनने के बाद ही यह सब हुआ या भाजपा शासन में भी चल रहा था।
- अब इन आरोपों पर चुप्पी क्यों?

शिमला/शैल। लगातार तीन चुनाव हार चुकी प्रदेश भाजपा क्या अपना राजनीतिक आधार बनाये रखने के लिये धर्म का सहारा लेने का प्रयास कर रही है? यह सवाल चम्बा के सलूणी में घटे मनोहर हत्याकाण्ड पर सामने आयी भाजपा की प्रतिक्रियाओं से उभरा है। इस हत्याकांड की हर एक ने निन्दा की है। क्योंकि इससे ज्यादा घिनौना और मानवता को शर्मसार करने वाला और कुछ हो ही नहीं सकता। यह काण्ड जैसे ही सामने आया पुलिस बिना कोई समय खोये इसकी जांच में जुट गयी और संदिग्धों को तुरन्त प्रभाव से पकड़ लिया गया। लेकिन जैसे ही यह सामने आया कि कथित दोषी मुस्लिम है तो इस पर तुरन्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह खुलासा रखा कि इस परिवार ने दो हजार के 97 लाख के नोट बदलवाये है और इनके खाते में दो करोड़ जमा है। इसने सौ बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। परिवार के पास बकरियां हैं और प्रतिवर्ष दो सौ बेचता है। निश्चित है कि जयराम ठाकुर को जो सूचना दी गयी उसी को पुख्ता मानकर उन्होंने यह बयान दे दिया। इस बयान से यह संदेश गया है कि यह सब कुछ इस परिवार ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर लिया और प्रशासन बेखबर बैठा रहा। जयराम ठाकुर के इस ब्यान के बाद राजस्व विभाग भी हरकत में आया जमीन की पैमाइश की गयी और तीन बीघा पर कब्जा पाया गया। लेकिन दो हजार के नोट बदलवाने और दो करोड़ खाते में जमा होने को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया और न ही इस आश्य का फिर से कोई ब्यान आया।

इस ब्यान के परिदृश्य में भाजपा नेता पूरे उत्तेजित वातावरण में यदि पीड़ित परिवार को मिलने दिये जाते तो उसके बाद किस तरह की कानून और व्यवस्था की स्थिति बन जाती इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस परिदृश्य यह जांच एनआईए को सौंपे जाने से न चाहते हुये भी आने वाले दिनों में प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम समस्या खड़ी हो जाती। जिस तरह के आरोप लगाये गये हैं उनकी आंच तो पूर्व के जयराम शासन तक भी चली जाती। यह सवाल उठता कि उस समय इस परिवार की गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गयी। क्योंकि सौ बकरियों का मालिक होकर दो सौ तो उस समय भी बेचता होगा। सौ बीघा पर अवैध कब्जा तो तब से चल रहा होगा। कुल मिलाकर इस हत्याकांड पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा नेतृत्व की आयी है उसे यही आभास होता है कि भाजपा राजनीति के लिये किसी भी हद तक जा सकती है। इस परिवर्तन में कानून और व्यवस्था को लेकर भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन भी सरकार से ज्यादा भाजपा के अपने ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि चालीस से अधिक हत्याओं और 150 बलात्कार का जो आंकड़ा उछालकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाया गया है वह भाजपा शासन में घटे 1500 बलात्कार के आंकड़ों से पूर्व शासन से ज्यादा सवाल पूछता है। इसलिये भाजपा पर यह सवाल बराबर बना रहेगा कि उसने राजनीतिक आधार को बचाने के लिये धर्म को भी मनोहर हत्याकाण्ड के माध्यम से एक हथियार के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया है। जबकि हिमाचल में इस तरह की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। बल्कि इन प्रतिक्रियाओं से मणिकरण प्रकरण के दौरान आयी प्रतिक्रियाएं फिर से यह जवाब मांगती है कि उस दौरान बनाये गये मामलों की आज क्या स्थिति है।